CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (PROF. M. G. K. MENON): (a) and b) As part of the effort to promote equality of educational opportunities for all, Government propose to expand educational opportunities in the rural areas during the VIIIth Five Year Plan. Strategies for this expansion at different levels of education are being worked out.

Issues like land and water use, land reform laws, environmental preservation and general health are alraedy dealt with in the curriculum for Social Sciences and Science at different stages of school education. Topics related to water use, environmental preservation and general health from part of the curriculum for the environmental studies at the primary stage. The Science curriculum at the upper-primary and secondary stages also deal with topics dealing with health and nutrition, protection of the environment and preservation of the eco system. The topics related to land and wateruse and environmental preservation are dealt with in the curriculum in Geography for Classes VIII *to* X. Topics on land reform are included in the curriculum for *Sociology* for Class XII.

न्यायमूर्ति जसवंत सिंह आयोग का प्रतिवेदन

*216. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :
श्री राम जेठमलानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यायमूर्ति, जसवंत सिंह आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का अध्ययन कर लिया है, जिसे 1985 में हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिये नियुक्त किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस आयोग के निष्कर्षों के अनुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) न्यायमूर्ति श्री जसवंत सिंह को जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत न्यायमूर्ति जसवंत सिंह आयोग के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था । उन्हें तो, कई संसद सदस्यों तथा हरियाणा विधान सभा के विधायकों द्वारा 4 जुलाई, 1985 को तत्कालीन प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन में निहित मामलों, जिनमें हरियाणा के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री भजन लाल तथा उनके संबंधियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगाए गए थे, की एक प्रारंभिक जांच करने के लिए केवल विशेष न्यायाधीश ही नियुक्त किया गया था । उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट अगस्त, 1985 में प्रस्तुत कर दी थी । अपनी रिपोर्ट में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि श्री भजन लाल तथा उनके निकट संबंधियों पर प्रथम-दृष्टया कोई मामला नहीं बनता ।

Self-sufficiency in Defence Production

*217. SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN; Will the PRIME MINISTER be pleased to state;

(a) whether Defence Production in our country is approaching self-sufficiency;

(b) if not, what steps are being taken to attain this objective;

(c) what is the percentage of the contribution of indigenous production in the overall Defence requirements of the country; and

(d) what is the foreign exchange component of our Defence expenditure?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. RAJA RAMANNA): (a) and (b) The objective of the Government is to achieve self-sufficiency in Defence production wherever it is technologically feasible and economically viable.